

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	आषाढ़ 27, गुरुवार शाके 1941-जुलाई 18, 2019 <i>Asadha 27, Thursday, Saka 1941-July 18, 2019</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 17, 2019

संख्या प.2(15)विधि/2/2019.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 जुलाई, 2019 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 13)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 जुलाई, 2019 को प्राप्त हुई)

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह 6 मार्च, 2019 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1973 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 5 का संशोधन.- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "आठ वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) परन्तुक के विद्यमान खण्ड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 2) के प्रारम्भ पर पद धारण कर रहे लोकायुक्त द्वारा, ऐसे प्रारम्भ से वह पद छोड़ा हुआ समझा जायेगा;" और

(iii) परन्तुक का विद्यमान खण्ड (ककक) हटाया जायेगा।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, July 17, 2019

No. F. 2 (15) Vidhi/2/2019.- In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Lokayukta Tatha Up-Lokayukta (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (2019 Ka Adhiniyam Sankhyank 13):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS (AMENDMENT) ACT,
2019**

(Act No. 13 of 2019)

(Received the assent of the Governor on the 17th day of July, 2019)

An

Act

further to amend the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 6th March, 2019.

2. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 9 of 1973.- In sub-section (1) of section 5 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973 (Act No. 9 of 1973), hereinafter referred to as the principal Act,-

- (i) for the existing expression "eight years" , the expression "five years" shall be substituted;
- (ii) for the existing clause (aa) of the proviso, the following clause shall be substituted, namely:-

"(aa) the Lokayukta holding office at the commencement of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance, 2019

(Ordinance No. 2 of 2019) shall be deemed to have demitted that office with effect from such commencement;"; and

(iii) the existing clause (aaa) of the proviso shall be deleted.

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 2 of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

महावीर प्रसाद शर्मा,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।